नईदुनिया

खास-खबरें

हाइड्रोजन ऊर्जा से चलेगा रोबोटिक घोड़ा, कावासाकी ला रही नई तकनीक

टोक्यो, एजेंसीः दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी कावासाकी भविष्य की परिवहन तकनीक को लेकर एक नया प्रयोग कर रही है। कंपनी हाइड्रोजन ऊर्जा से चलने वाला रोबोटिक घोड़ा विकसित कर रही है, जिसका नाम कोरलियो रखा गया है। यह वाहन पारंपरिक बाइक और कार से अलग चार पैरों वाली रोबोटिक प्रणाली पर आधारित है। कावासाकी का यह प्रोटोटाइप भविष्य की मोबिलिटी के नए विकल्प के रूप में पेश किया जा रहा है। इसमें हाइड्रोजन ईंधन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे इसे पर्यावरण के अनुकूल परिवहन माध्यम बनाने की कोशिश की जा रही है।

कोरलियो में चार रोबोटिक पैर दिए गए हैं, जो इसे असमान सतहों पर चलने में सक्षम बना सकते हैं। यह तकनीक पहाड़ी क्षेत्रों, कठिन रास्तों और ऐसे स्थानों पर उपयोगी हो सकती है, जहां सामान्य वाहन आसानी से नहीं पहुंच पाते। कंपनी के अनुसार, इस तरह के रोबोटिक वाहन भविष्य में परिवहन के तरीके को बदल सकते हैं। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आधुनिक नियंत्रण प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है, जिससे वाहन की गति और संतुलन को बेहतर बनाया जा सके। हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा को भविष्य के स्वच्छ ईंधन विकल्पों में शामिल किया जाता है।

एलआईसी को एचडीएफसी बैंक में हिस्सेदारी बढ़ाने की मंजूरी

नईदुनिया ब्यूरो, मुंबईः भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को एचडीएफसी बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से मंजूरी मिल गई है। इस मंजूरी के बाद एलआईसी बैंक में अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीद सकेगा। इस घटनाक्रम के बाद एचडीएफसी बैंक के शेयरों पर निवेशकों की नजर बनी हुई है। आरबीआई के नियमों के अनुसार, किसी बैंक में बड़ी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए नियामकीय मंजूरी जरूरी होती है। एलआईसी ने एचडीएफसी बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए आवेदन किया था, जिसे अब केंद्रीय बैंक ने स्वीकृति दे दी है। एलआईसी देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है और एचडीएफसी बैंक देश के प्रमुख निजी बैंकों में शामिल है। दोनों संस्थानों का भारतीय वित्तीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। हिस्सेदारी बढ़ने से एलआईसी की बैंक में भागीदारी और मजबूत होगी। आरबीआई की मंजूरी के बाद एलआईसी को निर्धारित अवधि के भीतर एचडीएफसी बैंक के अतिरिक्त शेयर खरीदने होंगे। हालांकि, हिस्सेदारी खरीदने की प्रक्रिया और बाजार से शेयरों की खरीद का तरीका कंपनी की रणनीति पर निर्भर करेगा।

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, किसी बड़े संस्थागत निवेशक की हिस्सेदारी बढ़ना कंपनी के प्रति दीर्घकालिक भरोसे का संकेत माना जाता है। एलआईसी जैसी बड़ी संस्था के निवेश से एचडीएफसी बैंक में निवेशकों की रुचि बढ़ सकती है। एचडीएफसी बैंक देश के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंकों में से एक है और इसका कारोबार बैंकिंग, ऋण वितरण तथा वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में फैला हुआ है। वहीं एलआईसी लंबे समय से भारतीय वित्तीय बाजार में एक प्रमुख संस्थागत निवेशक के रूप में सक्रिय है। आरबीआई की मंजूरी के बाद अब एलआईसी और एचडीएफसी बैंक से जुड़े इस सौदे पर बाजार की नजर रहेगी।

चीनी की जमाखोरी पर सरकार सख्त स्टॉक सीमा घटाकर 15 दिन की

त्यौहारी सीजन से पहले लिया फैसला, 1 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगा नया नियम

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः त्यौहारी सीजन से पहले केंद्र सरकार ने चीनी की जमाखोरी रोकने के लिए स्टॉक सीमा घटा दी है। अब थोक व्यापारियों और डीलरों को 15 दिन से अधिक का चीनी भंडार रखने की अनुमति नहीं होगी। नया नियम 1 सितंबर से लागू होकर 30 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा।

सरकार ने इससे पहले अगस्त की शुरुआत में चीनी डीलरों के लिए 30 दिन की स्टॉक सीमा तय की थी। अब इसे घटाकर 15 दिन कर दिया गया है। नए नियम के तहत महीने में 10 मीट्रिक टन से अधिक चीनी का कारोबार या उपयोग करने वाले थोक व्यापारी, डीलर और संबंधित कारोबारी तय सीमा से अधिक स्टॉक नहीं रख सकेंगे।

इस व्यवस्था के दायरे में मिठाई विक्रेता, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, शीतल पेय निर्माता और अन्य बड़े खरीदार भी शामिल होंगे। सरकार का उद्देश्य त्योहारी सीजन के दौरान

बढ़ने वाली चीनी की मांग के बीच जमाखोरी पर रोक लगाना और बाजार में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

सरकार स्टॉक सीमा के पालन पर निगरानी भी रखेगी। व्यापारियों और थोक खरीदारों की पहचान पिछले एक वर्ष की औसत मासिक खपत के आधार पर की जाएगी। चीनी मिलों से बड़े खरीदारों को सीधे या डीलरों के माध्यम से होने वाली बिक्री की भी निगरानी की जाएगी।

बिक्री और खपत का सत्यापन वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न तथा चीनी के एचएसएन कोड के आधार पर किया जाएगा। इसके जरिए यह पता लगाने का प्रयास होगा कि कारोबारियों के पास निर्धारित सीमा से अधिक चीनी का भंडार तो नहीं है।

सरकार का यह फैसला ऐसे समय आया है जब चीनी की खुदरा कीमतों में तेजी देखी गई है। अगस्त से नवंबर के बीच त्योहारी मांग बढ़ने के कारण चीनी की खपत बढ़ने की संभावना रहती है। हाल के आंकड़ों के अनुसार, एक महीने में चीनी की खुदरा कीमत में करीब 13 से 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

केंद्र और राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन तथा स्थानीय निकायों को इस स्टॉक सीमा के दायरे से बाहर रखा गया है। सरकार के अनुसार, स्टॉक सीमा घटाने का उद्देश्य चीनी की जमाखोरी रोकना, बाजार में उपलब्धता बढ़ाना और कीमतों पर नियंत्रण बनाए रखना है।

इंडियन ऑयल ने अल्जीरिया से एलपीजी आयात का समझौता किया

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अल्जीरिया की सरकारी कंपनी सोनाट्रैक के साथ वर्ष 2027 के लिए एलपीजी यानी रसोई गैस आयात का समझौता किया है। इस समझौते के तहत भारत को हर महीने 45 हजार से 55 हजार टन तक एलपीजी की आपूर्ति की जाएगी। भारत ने यह कदम रसोई गैस की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने और खाड़ी देशों पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से उठाया है। इस समझौते के तहत आने वाली गैस में प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण शामिल होगा। यह सौदा फ्री-ऑन-बोर्ड आधार पर किया गया है, जिसमें जहाज पर गैस लोड होने के बाद आगे की जिम्मेदारी इंडियन ऑयल की होगी।

भारत ने यह फैसला उस समय लिया है, जब अंतरराष्ट्रीय तनाव के कारण ईंधन आपूर्ति पर असर पड़ने की चिंता बढ़ी है। इस वर्ष अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के दौरान होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते गैस आपूर्ति प्रभावित हुई थी। इसके कारण भारत में ईंधन उपलब्धता को लेकर दबाव बढ़ गया था।

अल्जीरिया से होने वाली एलपीजी आपूर्ति भारत के लिए आर्थिक रूप से भी लाभदायक मानी जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार, अल्जीरिया से मिलने वाली गैस की कीमत सऊदी अरब की कंपनी सऊदी अरामको की तुलना में कम है। इस समझौते से इंडियन ऑयल और सोनाट्रैक के बीच पुराना व्यापारिक संबंध भी दोबारा मजबूत होगा।

भारत अब एलपीजी आयात के लिए नए देशों के साथ संबंध बढ़ा रहा है। जून से अल्जीरिया से दोबारा गैस आयात शुरू किया गया है। अगस्त में वहां से करीब 1.10 लाख टन गैस आने की उम्मीद है।

इसके अलावा भारत अमेरिका से भी एलपीजी आयात बढ़ाने की योजना बना रहा है। वर्ष 2027 तक देश की जरूरत का 25 प्रतिशत हिस्सा अमेरिका से लेने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम संयुक्त निविदा की तैयारी कर रही हैं।

टीसीएस पर कर्मचारियों की निगरानी का आरोप, कंपनी ने दी सफाई

▸▸ कंपनी बोली- व्यक्तिगत गतिविधियों पर नजर नहीं, नेटवर्क और सिस्टम की कार्यक्षमता की हो रही निगरानी

नईदुनिया ब्यूरो, मुंबईः देश की प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी टीसीएस कर्मचारियों की निगरानी को लेकर चर्चा में है। रिपोर्टों के अनुसार, कंपनी कर्मचारियों के लैपटॉप और कार्यस्थलों पर निगरानी उपकरणों का इस्तेमाल कर रही है। हालांकि, टीसीएस ने कहा है कि इन उपकरणों का उद्देश्य कर्मचारियों की व्यक्तिगत गतिविधियों पर नजर रखना नहीं, बल्कि नेटवर्क की समग्र कार्यक्षमता और प्रणाली की सुरक्षा बेहतर करना है। विवाद की मुख्य वजह निगरानी उपकरणों की पहुंच को लेकर है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि टीसीएस के निगरानी उपकरण अनुप्रयोग स्तर तक की जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके बाद यह सवाल उठने लगा कि क्या इन उपकरणों के जरिए कर्मचारियों की व्यक्तिगत गतिविधियों का भी विस्तृत रिकॉर्ड रखा जा रहा है। टीसीएस ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि उसकी निगरानी व्यवस्था व्यापक स्तर पर नेटवर्क की कार्यक्षमता से संबंधित जानकारी तक सीमित है। कंपनी ने स्पष्ट किया कि वह व्यक्तिगत कर्मचारियों की गतिविधियों को ट्रैक नहीं करती। कार्यस्थल पर कर्मचारियों की निगरानी का मुद्दा वैश्विक प्रौद्योगिकी उद्योग में पहले भी विवाद का कारण बन चुका है। मेटा को भी एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े प्रोजेक्ट के दौरान कर्मचारियों की निगरानी को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ा था। कंपनी के एक तंत्र में कर्मचारियों के कीबोर्ड पर दबाए गए बटनों और माउस की गतिविधियों से संबंधित आंकड़े एकत्र किए जा सकते थे। विरोध के बाद कर्मचारियों को आंकड़े एकत्र करने से बाहर रहने का विकल्प दिया गया था। तकनीकी रूप से व्यापक स्तर की निगरानी में नेटवर्क पर भार, इंटरनेट की गति और संभावित साइबर हमले या तकनीकी खराबी जैसी जानकारी देखी जाती है।

दूरदराज गांवों तक इंटरनेट पहुंचाएगा स्टारलिंक, लाइसेंस के लिए फिर आवेदन

भारत के 11 हजार से अधिक गांवों में 4जी नेटवर्क नहीं, ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधारने की योजना

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः स्टारलिंक ने भारत में दूरदराज और ग्रामीण इलाकों तक इंटरनेट पहुंचाने की योजना के तहत लाइसेंस के लिए दोबारा आवेदन किया है। कंपनी के प्रमुख इलॉन मस्क ने शुक्रवार को कहा कि स्टारलिंक भारत के उन लोगों की मदद कर सकता है, जिन्हें अब तक पर्याप्त इंटरनेट सुविधा नहीं मिल पाई है। उन्होंने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सुधारने की बात कही।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, मई 2026 तक भारत के 11 हजार से अधिक सूचीबद्ध गांवों में 4जी नेटवर्क की पहुंच नहीं थी। मार्च 2026 तक देश में कुल 109.3 करोड़ इंटरनेट सदस्य थे, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों के 44.08 करोड़ सदस्य शामिल थे। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 100 लोगों पर 48.31 इंटरनेट कनेक्शन हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में

यह संख्या 126.80 है।

सरकार की भारतनेट योजना के तहत देश में 8.5 लाख रूट किलोमीटर से अधिक फाइबर बिछाया जा चुका है। इससे करीब 2.21 लाख ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार किया गया है। हालांकि, जून 2026 तक केवल 80,472 ग्राम पंचायतों में ही पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस चालू हो पाए थे। मस्क के अनुसार, स्टारलिंक की उपग्रह आधारित तकनीक दूरदराज गांवों, पहाड़ी क्षेत्रों, द्वीपों, कम बुनियादी ढांचे वाले इलाकों और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंचाने में उपयोगी हो सकती है। यह तकनीक जमीन पर मोबाइल टावर लगाने के बजाय पृथ्वी की निचली कक्षा में मौजूद उपग्रहों के माध्यम से इंटरनेट उपलब्ध कराती है।

स्टारलिंक भारत में उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने के लिए सरकार से बातचीत कर रही है। हाल में कंपनी की मंजूरी प्रक्रिया रुकने की खबरें सामने आई थीं, जिनमें सुरक्षा और भू-राजनीतिक चिंताओं का उल्लेख किया गया था। स्टारलिंक की व्यावसायिक संचालन संबंधी उपाध्यक्ष लॉरेन ड्रेयर ने इन खबरों का खंडन करते हुए कहा कि कंपनी भारत सरकार के साथ लगातार सकारात्मक बातचीत कर रही है। कंपनी के आवेदन के बाद अब भारत में उसकी उपग्रह इंटरनेट सेवा शुरू करने की दिशा में आगे की मंजूरियों और स्पेक्ट्रम आवंटन की प्रक्रिया पर नजर रहेगी।

इंडिगो वेबसाइट फिर ठप, टिकट बुकिंग व वेब चेक-इन प्रभावित

आई तकनीकी दिक्कत, एप लॉगिन और भुगतान में भी परेशानी,एक सप्ताह में दूसरी बार

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की वेबसाइट शुक्रवार को फिर ठप हो गई। कई यात्रियों को वेबसाइट के जरिए उड़ान की टिकट बुक करने, वेब चेक-इन करने और भुगतान करने में परेशानी हुई। कुछ उपयोगकर्ताओं ने मोबाइल एप में लॉगिन नहीं कर पाने की शिकायत भी की। एक सप्ताह में दूसरी बार इंडिगो की ऑनलाइन सेवाओं में तकनीकी समस्या सामने आई है।

वेबसाइट पर उड़ान की बुकिंग करने के दौरान कुछ उपयोगकर्ताओं को नो डेटा अवेलेबल का संदेश दिखाई दिया। एयरलाइन ने अपनी वेबसाइट पर सेवा संबंधी सूचना जारी करते हुए कहा कि प्रणाली में रुक-रुककर समस्या आ रही है। इससे कुछ ग्राहकों को ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल करने में परेशानी हो सकती है। कंपनी की तकनीकी टीमें समस्या को जल्द दूर करने में जुटी हैं।

इंडिगो ने यात्रियों से कुछ समय बाद अपने डिजिटल माध्यमों का दोबारा इस्तेमाल करने की सलाह दी है। जिन यात्रियों को तत्काल यात्रा संबंधी सहायता की आवश्यकता है, उन्हें ग्राहक सहायता केंद्र से संपर्क करने को कहा गया है। बाद में यात्रा करने वाले यात्रियों से कुछ समय बाद दोबारा प्रयास करने की अपील की गई है।

शुक्रवार को कई यात्रियों ने इंटरनेट मीडिया पर उड़ान की टिकट बुकिंग विफल होने, वेब चेक-इन नहीं होने और भुगतान की पुष्टि नहीं मिलने की शिकायत की। इससे दो दिन पहले भी इंडिगो ने अपने आरक्षण तंत्र में रुक-रुककर समस्या आने की जानकारी दी थी। एयरलाइन ने तब बताया था कि वह अपने प्रौद्योगिकी साझेदार के साथ मिलकर समस्या दूर करने का प्रयास कर रही है। घरेलू विमानन बाजार में जुलाई के दौरान इंडिगो की हिस्सेदारी करीब 67 प्रतिशत थी। ऐसे में उसके डिजिटल तंत्र में तकनीकी समस्या आने से बड़ी संख्या में यात्रियों की टिकट बुकिंग, चेक-इन और आरक्षण प्रबंधन प्रभावित हो सकता है। हालांकि, शुक्रवार को सामने आई तकनीकी समस्या की अवधि और इसके वास्तविक कारण के बारे में एयरलाइन की ओर से विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है।

24 अगस्त से नौ सिम के बाद नया कनेक्शन नहीं मिलेगा

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः देश में अब एक व्यक्ति के नाम पर तय सीमा से अधिक मोबाइल सिम कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार कंपनियों को निर्देश दिया है कि जिन ग्राहकों के नाम पर पहले से नौ मोबाइल कनेक्शन सक्रिय हैं, उन्हें नया सिम कार्ड जारी न किया जाए। यह व्यवस्था 24 अगस्त से देशभर में लागू होगी।

दूरसंचार विभाग के अनुसार, यदि कोई ग्राहक नौ सिम कार्ड की सीमा पूरी होने के बाद नया कनेक्शन लेने पहुंचता है तो दूरसंचार कंपनी उसे नया सिम देने से मना करेगी। ग्राहक को यह भी बताया जाएगा कि उसके नाम पर पहले से अधिकतम संख्या में मोबाइल कनेक्शन सक्रिय हैं। अलग-अलग कंपनियों से सिम लेने पर भी यह सीमा लागू रहेगी। सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है। नया सिम सक्रिय करने से पहले कंपनियां इस प्रणाली के माध्यम से जांच करेंगी कि संबंधित व्यक्ति के नाम पर कुल कितने मोबाइल कनेक्शन पहले से सक्रिय हैं। सरकार 23 अगस्त से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नया प्रावधान भी जोड़ रही है।

सेंसेक्स मामूली बढ़त के साथ बंद, निफ्टी में 20 अंकों की तेजी

धातु कंपनियों के शेयरों में रही खरीदारी, घरेलू निवेशकों ने सात दिन में लगाए 15 हजार करोड़

नईदुनिया ब्यूरो, मुंबईः भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को लगभग सपाट स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स में मामूली तीन अंकों की बढ़त रही और यह 77,540 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 20 अंक चढ़कर 24,252 के स्तर पर पहुंच गया। बाजार में सबसे ज्यादा खरीदारी धातु क्षेत्र के शेयरों में देखने को मिली।

एशियाई बाजारों में शुक्रवार को कारोबार मिला-जुला रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी सूचकांक 60 अंक की बढ़त के साथ 6913 के स्तर पर बंद हुआ। हांगकांग का हैंगसेंग 311 अंक बढ़कर 26009 के स्तर पर पहुंचा। वहीं जापान का निक्केई 200 अंक गिरकर 66016 के स्तर पर बंद हुआ। इससे पहले 20 अगस्त को अमेरिकी बाजारों में गिरावट दर्ज की गई थी। डाउ जोंस 704 अंक गिरकर 52759 के स्तर पर बंद हुआ था। नैस्डैक में 264 अंकों की गिरावट रही और यह 26067 के स्तर पर बंद हुआ। एसएंडपी 500 भी 67 अंक फिसलकर 7641 के स्तर पर रहा।

घरेलू संस्थागत निवेशकों ने बाजार में लगातार खरीदारी जारी रखी। आंकड़ों के अनुसार, पिछले सात कारोबारी दिनों में घरेलू निवेशकों ने 15,192 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे हैं। वहीं विदेशी संस्थागत निवेशकों ने इस अवधि में 1,059 करोड़ रुपये की बिकवाली की है। इससे पहले 20 अगस्त को शेयर बाजार में तेजी रही थी। सेंसेक्स 628 अंक चढ़कर 77,538 के स्तर पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी में 154 अंकों की बढ़त दर्ज की गई थी और यह 24,232 के स्तर पर बंद हुआ था। शुक्रवार के कारोबार में बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया। धातु क्षेत्र के शेयरों में खरीदारी ने बाजार को मजबूती दी।

स्पेशल खबर एवरग्रैंड की दिवालिया प्रक्रिया को मंजूरी, संस्थापक को उम्रकैद

28 लाख करोड़ के कर्ज में डूबी चीन की दिग्गज रियल एस्टेट कंपनी का साम्राज्य ढहा

बीजिंग, एजेंसीः चीन की दिग्गज रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रैंड की दिवालिया प्रक्रिया को अदालत ने मंजूरी दे दी है। कंपनी पर करीब 300 अरब डॉलर यानी लगभग 28 लाख करोड़ रुपये का कर्ज था। इससे पहले कंपनी के संस्थापक हुई का यान को वित्तीय धोखाधड़ी और गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने उनकी निजी संपत्ति जब्त करने और राजनीतिक अधिकार समाप्त करने का भी आदेश दिया है।

गुआंगझू की अदालत ने गुआंगझू रूरल कॉमर्शियल बैंक की याचिका पर कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया। अदालत ने माना कि एवरग्रैंड अपने कर्ज चुकाने में

पूरी तरह असमर्थ है और उसकी कुल संपत्ति देनदारियों की तुलना में काफी कम है। इसके साथ कंपनी को बंद करने की कानूनी प्रक्रिया भी शुरू हो गई।

कभी दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों में शामिल एवरग्रैंड ने कर्ज लेकर जमीन खरीदने और निर्माण पूरा होने से पहले ही मकान बेचने का कारोबार मॉडल अपनाया था। ग्राहकों से मिलने वाले अग्रिम भुगतान से कंपनी नए प्रोजेक्ट शुरू करती थी। वर्ष 2018 में एवरग्रैंड ब्रांड मूल्य के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी बनी थी। उस समय उसका ब्रांड मूल्य 16.2 अरब डॉलर था।

कंपनी के पतन की शुरुआत वर्ष 2020 में चीन सरकार की थ्री रेड लाइन्स नीति लागू होने के बाद हुई। इस नीति के तहत अत्यधिक कर्ज लेने वाली रियल एस्टेट कंपनियों पर नियंत्रण बढ़ाया गया। एवरग्रैंड को सस्ता कर्ज मिलना बंद हुआ और मकानों की बिक्री घटने से उसका नकदी प्रवाह प्रभावित हुआ। कंपनी के 280 शहरों में 1,300 से अधिक प्रोजेक्ट अधूरे पड़े थे। परिसमापन प्रक्रिया के तहत संपत्तियां बेचकर कर्जदाताओं का पैसा लौटाने का प्रयास किया गया, लेकिन वसूली की राशि कर्ज की तुलना में बेहद कम रही। एवरग्रैंड के शेयरों का कारोबार लंबे समय तक बंद रहने के बाद अगस्त 2025 में उन्हें हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिया गया था।

विशेषज्ञों के अनुसार एवरग्रैंड का संकट 2008 के लेहमैन ब्रदर्स संकट जैसा वैश्विक वित्तीय संकट नहीं बना, क्योंकि चीन सरकार ने इसे नियंत्रित तरीके से संभाला। हालांकि इससे चीन के रियल एस्टेट, निर्माण क्षेत्र, स्टील और सीमेंट की मांग तथा स्थानीय सरकारों की आय पर असर पड़ा। यह मामला अत्यधिक कर्ज पर आधारित विकास मॉडल के जोखिम को भी सामने लाता है।

6जी की तैयारी के बीच 4जी फोन अब भी उपयोगी विकल्प

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः भारत में 6जी तकनीक की तैयारी के बीच मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए 4जी और 5जी फोन को लेकर सवाल बना हुआ है। इस समय देश में 5जी नेटवर्क का विस्तार तेजी से हो रहा है, लेकिन कई क्षेत्रों में अभी भी 4जी नेटवर्क की पहुंच और उपलब्धता अधिक है। ऐसे में नया मोबाइल फोन खरीदने वालों के लिए 4जी फोन अभी भी उपयोगी विकल्प बना हुआ है।

भारत में दूरसंचार कंपनियां 5जी सेवाओं का विस्तार कर रही हैं। हालांकि, 5जी नेटवर्क की उपलब्धता सभी क्षेत्रों में समान नहीं है। कई ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में अभी 4जी नेटवर्क ही प्रमुख कनेक्टिविटी माध्यम है। ऐसे में केवल 5जी की उपलब्धता को ध्यान में रखकर फोन खरीदना हर उपयोगकर्ता के लिए जरूरी नहीं है। दूसरी ओर, भारत में अगली पीढ़ी की मोबाइल तकनीक 6जी को लेकर भी तैयारी शुरू हो चुकी है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में इस बार 6जी तकनीक पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इससे देश में भविष्य की तेज और उन्नत मोबाइल सेवाओं की दिशा में काम बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, फोन खरीदते समय उपयोगकर्ता को अपने क्षेत्र में उपलब्ध नेटवर्क, इंटरनेट इस्तेमाल की जरूरत और बजट को ध्यान में रखना चाहिए। यदि किसी क्षेत्र में 5जी नेटवर्क की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है और सामान्य इंटरनेट उपयोग ही करना है तो 4जी फोन अभी भी व्यावहारिक विकल्प हो सकता है।